



P. Abhimanyu
General Secretary

BSNL EMPLOYEES UNION

Central Head Quarters

Ph.: 011-25705385
Fax : 011-25894862

Main Recognised Representative Union.
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar,
Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110008
E-mail : bsnleuchq@gmail.com, Website : www.bsnleu.in

बीएसएनएलईयू / 100 (सीएचक्यू)

18.06.2020

प्रति

(1) श्री अंशु प्रकाश,
सचिव, दूरसंचार,
दूरसंचार विभाग,
संचार मंत्रालय, संचार भवन,
20, अशोका रोड, नई दिल्ली - 110 001

(2) श्री पी.के. पुरवार,
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,
भारत संचार निगम लिमिटेड,
भारत संचार भवन, जनपथ,
नई दिल्ली - 110001.

आदरणीय महोदय,

विषय - धरना कार्यक्रम के आयोजन के लिए सूचना - संभदित.

धरना कार्यक्रम के आयोजन के लिए यह नोटिस जारी कि गयी है, जिसमें सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए दिनांक 26.06.2020 पर निम्नलिखित मुद्दों को निपटाने की मांग.

मांगे

बीएसएनएल की 4 जी सेवा को शुरू करने में अक्षम्य देरी।

बीएसएनएल की 4 जी सेवा के शुरू होने में देरी से कंपनी के पुनरुद्धार में भारी बाधा आ रही है। 4 जी उपकरणों की खरीद के लिए बीएसएनएल द्वारा जारी निविदा, निहित स्वार्थों द्वारा रची गई साजिश के परिणामस्वरूप ठप हो गई है। यह खेदजनक है कि सरकार TEPC द्वारा उठाए गए नाहक आपत्तियों को अनुचित महत्व दे रही है। "मेक इन इंडिया पॉलिसी" को लागू करने के लिए बीएसएनएल को बाध्य करके उसे छदमवेश पहना के उसके आड़ में बीएसएनएल को निजी दूरसंचार प्रदाताओं जैसे सही स्तर के मुकाबलों से वंचित रखा जा रहा है। इसलिये यह मांग की जाती है कि भारत सरकार तुरंत BSNL को तत्काल मंजूरी जारी करे, ताकि पहले से ही मंगाई गई निविदा के अनुसार 4 जी उपकरणों की खरीद की जा सके।

BSNL के पुनरुद्धार पैकेज का गैर-कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा BSNL के पुनर्जीवन पैकेज की घोषणा करके लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। इस पैकेज के अनुसार, 79,000 कर्मचारी VRS के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। VRS के मुद्दे के अलावा, पुनर्जीवन पैकेज में आश्वासन दिए गए अन्य कोई उपाय अबतक लागू नहीं किये गए हैं। BSNL की 4 जी सेवा शुरू करने हेतु, बाजार से धन जुटाने के लिए बीएसएनएल को संप्रभुता गारंटी जारी करने, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण इत्यादि जैसे बहुत प्रचारित किए गए उपाय अभी भी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। यह मांग की जाती है कि सरकार को बीएसएनएल के पुनर्जीवन के उपायों को लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए, जैसा कि पुनर्जीवन पैकेज में आश्वासित किया गया था।

बीएसएनएल प्रबंधन BSNLEU द्वारा उठाए गए मुद्दों का निपटारा करने में असफल

बीएसएनएल के मुख्य मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि संघटन, कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए प्रबंधन को लगातार लिख रहा है। हालाँकि, इन मुद्दों पर बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना बल्कि BSNLEU द्वारा

लिखे गए पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यह खेदजनक है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारा करने के लिए बीएसएनएल प्रबंधन कोई भी रुचि नहीं दिख रही है। अंतः यह मांग की जाती है कि बीएसएनएल प्रबंधन ने निम्नलिखित मुद्दों को निपटाने के लिए तत्काल सुनिश्चित कदम उठाने चाहिए।

- (1) कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बीएसएनएल प्रबंधन की आखरी प्राथमिकता बन गयी है। मई, 2020 के महीने के लिए वेतन भुगतान अब तक नहीं किया गया है। वेतन का समय पर भुगतान हर महीने सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (2) कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की मजदूरी के पैसों का पिछले एक साल से भुगतान नहीं किया गया है। बीएसएनएल प्रबंधन ने लॉक-डाउन अवधि के लिए श्रम और वित्त मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है। ठेका मजदूरों की बड़े पैमाने पर छंटनी प्रबंधन द्वारा की जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र स्तर पर संचालन और रखरखाव कार्यों को गंभीरता से बाधित कर सकती है। यह मांग की जाती है कि ठेका श्रमिकों के मजदूरी बकाया को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए और आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेका श्रमिकों के छंटनी को रोक दिया जाना चाहिए।
- (3) DoT के पत्र संख्या 36-11 / 2015-SR दिनांक 6 दिसंबर, 2016 के आधार पर, डाक विभाग ने पहले से ही एक योजना बनाई है, जिसके अनुसार कर्मचारी Covid -19 के वजहसे मृत्यु होनेवाले कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। BSNLEU ने सबसे पहले ही मांग की है कि इस योजना को BSNL में भी लागू किया जाना चाहिए। यह मांग काफी महत्वपूर्ण है और प्रबंधन को इसे लागू करने के लिए शीघ्र ही शुरुआती कदम उठाने चाहिए।
- (4) नॉन एग्जीक्यूटिव के वेज संशोधन (3rd PRC) के लिए वार्ता संयुक्त समिति में शुरू हो चुकी थी। हालांकि, इसे कोई भी वैध कारण के बिना ही बंद कर दिया गया है। अब यह मांग की जाती है कि नॉन एग्जीक्यूटिव के वेज के संशोधन (PRC) के लिए वार्ता को तुरंत फिर से शुरू करना चाहिए।
- (5) BSNLEU ने 31.01.2020 के मौजूद रिक्तियों के आधार पर पहले से ही विभिन्न सीमित आंतरिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं (LICE) की मांग की है। प्रबंधन को 31.01.2020 को मौजूद रिक्त पदों के आधार पर JTO LICE , JAO LICE, JTO (OL) LICE JE LICE , Telecom Technician LICE और JE (Civil) को JTO (Civil) के लिए शुरुआती कदम तुरंत उठाने चाहिए।
- (6) 26.05.2019 को आयोजित JTO (LICE) के लिए योग्यता मानकों में छूट देने के लिये पहले ही BSNLEU द्वारा मांग की जा चुकी है। यह मांग सही कारणों के आधार पर ही उठाई गई है। हम यह मांग करते हैं कि BSNL प्रबंधन इस मुद्दे को जल्द ही उसे निपटाना चाहिए।
- (7) JTO LICE परीक्षा के परिणाम जो पंजाब सर्कल से संबंधित थे उसे अबतक घोषित नहीं किए गए हैं। प्रबंधन को कानूनी बाधाओं को हटाने और परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने के लिए शुरुआती कदम उठाना चाहिए।
- (8) दूरसंचार कारखानों को क्षेत्रीय मंडल के साथ विलय कर दिया गया है। यह मांग की जाती है कि मुंबई, कोलकाता और जबलपुर दूरसंचार कारखानों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए एक अलग से दूरसंचार कारखाना सर्कल बनाया जाना चाहिए।
- (9) ग्रुप टर्म इंश्योरेंस (Group Term Insurance) पहले से ही अधिकारियों के लिए लागू किया गया है, यह सुविधा नॉन एग्जेक्यूटिव कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। BSNLEU काफी समय से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है।

- (10) पहले से ही कर्मचारियों के वेतन से एलआईसी प्रीमियम की कटौती की गई। लेकिन अभी तक यह कटौतियां एलआईसी को नहीं भेजी गयी है। जिसके कारण कर्मचारियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है, खासकर Covid -19 के इस कठिन समय के दौरान। बीएसएनएल प्रबंधन को ऐसे महत्वपूर्ण विषय में बिना किसी और देरी से इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए।
- (11) कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई सोसाइटी की बकाया राशि को भी अबतक संभदित सोसाइटी को भेजी नहीं गयी है, जो कर्मचारियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है और उसे दौहरी मार झेलनी पड़ रही है। प्रबंधन को तुरंत इस मुद्दे को निपटाना चाहिए।
- (12) कर्मचारियों को बीएसएनएल के BSNL MRS मेडिकल सुविधा के अनुसार अस्पतालों से नकद रहित (cash less) उपचार नहीं मिल रहा है। यह Covid -19 के प्रकोप के चलते कर्मचारियों को गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। प्रबंधन को तुरंत यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि कर्मचारियों को BSNL MRS के तहत विभिन्न मान्यताप्राप्त अस्पतालों से नकद रहित उपचार मिल जाना चाहिए जो उसका मूलभूत अधिकार है।
- (13) आगे, Covid -19 द्वारा होनेवाले खतरे को देखते हुए, यह मांग की जाती है कि प्रबंधन को आउटडोर उपचार के लिए निर्धारित सीलिंग (basic + DA) को कम करके 23 दिनों बजाय 15 दिन करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया गया है उसे तुरंत वापस लेना चाहिए।
- (14) प्रबंधन द्वारा SLA के आधारित आउटसोर्सिंग के कार्यों के लिए पहले ही आदेश जारी किए हैं। ठेकेदारों द्वारा कुछ हातचलाखी (manipulation) करने की कई स्थानों से रिपोर्ट आ रही है। यह BSNL के लिये काफी मंहगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए, यह मांग की जाती है कि प्रबंधन को SLA आधारित आउटसोर्सिंग कार्यों की खुद वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा करनी चाहिए।
- (15) 7 वे केंद्रीय वेतन आयोग के शिफारिशों के आधार पर नैमित्तिक (Casual) मजदूरों की मजदूरी को संशोधित (revised) करें।

धन्यवाद,

आपका कृपाभिलाषी



(पी। अभिमन्यू)
महासचिव

प्रतिलिपी :-

- (1) डॉ। पी.के मिश्रा, प्रधान मंत्रीजी के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011
- (2) श्री राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110 004
- (3) व्यक्तिगत सचिव, माननीय संचार मंत्रीजी, संचार भवन, नई दिल्ली- 110 001
- (4) सुश्री शशि नेगी, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -100001
- (5) श्री अरविंद वडनेरकर, निदेशक (मानव संसाधन), BSNL, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 107
- (6) श्री ए.एम. गुप्ता, महाप्रबंधक (एस आर), BSNL कॉर्पोरेट ऑफिस, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001